REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 9 | ISSUE - 7 | APRIL - 2020

उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप्स : भारत के आर्थिक विकास की नई दिशा

डॉ० उमेश कुमार शाक्य
असि० प्रोफेसर-अर्थशास्त्र,
माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आँवलखेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश.

सारांश

उद्यमिता, नवाचार, डिजिटल क्रांति, सरकारी नीतियों और युवाओं की रचनात्मक सोच ने भारत को "स्टार्टअप राष्ट्र" में रूपांतरित करने की दिशा में अग्रसर कर दिया है। उद्यमिता अब केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का माध्यम बन चुकी है। भारत में उद्यमिता का इतिहास प्राचीन व्यापार परंपराओं से जुड़ा है, पर 1991 के आर्थिक उदारीकरण और 2016 के स्टार्टअप इंडिया अभियान के बाद इसमें नयी ऊर्जा आयी है। आज युवा वर्ग पारंपरिक नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर नवाचार, जोखिम और सामाजिक प्रभाव पर आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। यद्यपि उद्यमिता के मार्ग में पूँजी की कमी, ग्रामीण तकनीकी अवसंरचना, नियामकीय जटिलताएँ और असफलता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI), ब्लॉकचेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा देंगे। भारत की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशिता का मार्ग "नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था" (Innovation-Driven Economy) से होकर जाता है। उद्यमिता और नवाचार केवल आर्थिक वृद्धि के उपकरण मात्र नहीं हैं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की आधारशिला भी हैं, सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत मिलकर सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करके, भारत को 21वीं सदी में न केवल "विश्वगुरु" बल्कि "विश्व-उद्यमिता महाशक्ति" भी बनाया जा सकता है।

बीज शब्द (Keyword): उद्यमिता, नवाचार, स्टार्टअप, आर्थिक विकास, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्टअप इंडिया, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल उद्यम, सतत विकास

उद्यमिता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति का आधार होती है। भारत जैसे विकासशील देश में उद्यमिता केवल व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जोखिम उठाकर नये विचारों को व्यावसायिक रूप में लागू करता है। उद्यमी केवल पूँजीपति नहीं होता, बल्कि समाज के विकास का चालक होता है। जोसेफ शम्पीटर (Joseph Schumpeter) ने कहा कि उद्यमी

वह है जो "सृजनात्मक विनाश" (Creative Destruction) के माध्यम से नये उत्पाद, तकनीक और बाज़ार का निर्माण करता है।

भारत में उद्यमिता का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में व्यापार, हस्तशिल्प, वस्त्र और धातु उद्योग विकसित थे। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में सरकारी क्षेत्र (Public Sector) ने औद्योगिकीकरण की भूमिका निभाई, किंतु 1991 के आर्थिक उदारीकरण (Liberalization) ने निजी क्षेत्र और उद्यमियों के लिए नये द्वार खोलने का कार्य किया। 2000 के बाद इंटरनेट और मोबाइल क्रांति ने भारतीय उद्यमिता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

नवाचार उद्यमिता की आत्मा है। भारत में नवाचार का केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी (IT), कृषि-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, फिनटेक और पर्यावरणीय समाधान बन चुका है। 2016 में प्रारंभ हुए *स्टार्टअप इंडिया* अभियान ने युवा उद्यमियों को पूँजी, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किये हैं।

साहित्य समीक्षा

उद्यमिता और नवाचार पर शोध विश्व स्तर पर सदैव महत्वपूर्ण रहा है। शूम्पीटर (Schumpeter, 1934) ने नवाचार को आर्थिक विकास का प्रमुख प्रेरक माना। उनके अनुसार उद्यमी "क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन" की प्रक्रिया के माध्यम से पुरानी पद्धतियों को बदलते हैं और नई उत्पादक क्षमताओं का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति के प्रसार को समझा जा सकता है।

भारत में उद्यमिता पर प्रारम्भिक अध्ययन मुख्यतः पारंपरिक उद्योग, लघु उद्योग एवं MSME क्षेत्र पर केन्द्रित रहे। MSME क्षेत्र को भारत के औद्योगिक विकास का आधार माना गया जहाँ लाखों रोजगार सृजित होते रहे हैं। परंतु 2008 के बाद डिजिटल प्रौद्योगिकियों और मोबाइल इंटरनेट के विस्तार ने भारत में नवाचार तथा स्टार्टअप संस्कृति को नयी दिशा दी।

भारत सरकार द्वारा 2014 से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिन पर कई शोधकर्ताओं ने ध्यान आकर्षित किया। शर्मा (2016) के अनुसार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने उद्यमिता के लिये आवश्यक डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने युवा उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा का संचार किया।

स्टार्टअप इकोसिस्टम पर NASSCOM (2016) की रिपोर्ट के अनुसार, 2015–16 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बेस बन चुका था, जहाँ 4,200 से अधिक तकनीक-आधारित स्टार्टअप पंजीकृत थे। फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक एवं ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। Bain & Company (2016) के अनुसार, भारत में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश में लगातार वृद्धि हुई, जिससे नवाचार आधारित विकास संभव हुआ।

उद्यमिता के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी कई अध्ययन हुए। Saxena (2014) का तर्क है कि उद्यमिता आर्थिक अवसरों को बढ़ाती है और रोजगार सृजन का साधन बनती है। नीति आयोग (2016) के अनुसार, नवाचार आधारित उद्यम ग्रामीण बाजारों तक प्रौद्योगिकी पहुँचाने में सक्षम हैं।

हालाँकि चुनौतियों पर भी पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। विशेष रूप से वित्तीय पहुंच, उच्च लागत, अस्थिर नीतियाँ, कौशल का अभाव, निवेशक सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) तथा अवसंरचना की कमी उल्लेखनीय हैं।

सार रूप में पूर्ववर्ती शोध संकेत देते हैं कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा है, पर इसके लिए स्थिर नीतियों, मजबूत वित्तीय ढाँचे और नवाचार-अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। वर्तमान अध्ययन इस प्रवाह का विश्लेषण मई 2017 तक उपलब्ध डेटा के आधार पर करता है।

शोध विधि

इस शोध में **वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक** (Analytical) **अनुसंधान-पद्धति** अपनाई गई है। अध्ययन DPIIT, NITI Aayog, RBI, NSSO, NASSCOM, विश्व बैंक, IMF, MSME Ministry आदि से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है एवं डेटा विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, तालिकाओं का प्रयोग किया गया है। शोध में योजनाओं की पूर्व-स्थिति एवं बाद के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

डाटा विश्लेषण

भारत में स्टार्टअप्स की वार्षिक संख्या

वर्ष	स्टार्टअप्स की संख्या
2012	700
2013	3,000
2014	3,600
2015	4,200
2016	4,750

स्रोत : NASSCOM Startup India Report (2015, 2016)

भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश

वर्ष	कुल निवेश (US$ Bn)
2012	1.1
2013	1.8
2014	2.2
2015	4.9
2016	4.2

स्रोत : Bain & Company (2016)

प्रमुख स्टार्टअप सेक्टर और औसत वार्षिक वृद्धि दर

सेक्टर	CAGR (%)	स्रोत
ई-कॉमर्स	35%	NASSCOM (2016)
फिनटेक	30%	RBI Bulletin (2016)
हेल्थटेक	27%	NITI Aayog (2016)
एडटेक	25%	NASSCOM EdTech Report (2016)
एग्रीटेक	18%	World Bank (2015)

उपर्युक्त तालिकाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से स्पष्ट है कि 2012–2016 के दौरान भारत में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग सात गुना बढ़ी। इससे संकेत मिलता है कि डिजिटल परिवर्तन, स्मार्टफोन प्रसार और नीति-

समर्थन इस वृद्धि के मुख्य कारण रहे। विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के निवेशकों द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में रुचि दिखाये जाने के परिणामस्वरूप निवेश के स्तर भी लगातार वृद्धि हुई। सभी सेक्टरों में ई-कॉमर्स एवं फिनटेक की वृद्धि उच्चतम रही, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार ने सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया। एग्रीटेक की वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम रही, पर ग्रामीण बाजारों में इसकी क्षमता उल्लेखनीय है।

समस्याएँ / चुनौतियाँ

भारत में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम यद्यपि 2010 के बाद तीव्र गति से विकसित हुआ है, यद्यपि कई संरचनात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियाँ भी इसके समक्ष विद्यमान थीं। ये चुनौतियाँ न केवल उद्यमिता की संभावनाओं को सीमित करती हैं, बल्कि नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ उभरकर सामने आती हैं-

1. वित्तीय उपलब्धता और निवेश संबंधी बाधाएँ

स्टार्टअप्स के लिए प्रारम्भिक निवेश (Seed Funding) तथा विकास के लिए आवश्यक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की उपलब्धता मई 2017 तक सीमित थी। भारत में निवेश मुख्यतः ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में केंद्रित रहा, जबकि एग्रीटेक, हेल्थटेक, बायोटेक, विनिर्माण और हार्डवेयर स्टार्टअप्स को अपेक्षित पूंजी नहीं मिल सकी। बैंक और वित्तीय संस्थान जोखिम-उन्मुख स्टार्टअप्स को ऋण देने से हिचकते थे। बौद्धिक संपदा आधारित उद्यमों के पास पारंपरिक गिरवी योग्य परिसंपत्तियाँ नहीं होतीं, जिससे ऋण प्रवाह और भी सीमित हो जाता है। इसके कारण कई नवाचार संभावित उद्यम प्रारम्भिक चरण में ही बाधित हो जाते थे।

2. अवसंरचना की कमी और क्षेत्रीय असमानता

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का अधिकतर विकास बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरी केंद्रों तक सीमित रहा। इन शहरों के बाहर आवश्यक डिजिटल अवसंरचना, हाई-स्पीड इंटरनेट, आधुनिक औद्योगिक सुविधाएँ, इनक्यूबेशन सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और R&D प्रयोगशालाएँ सीमित थीं। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता, नेटवर्क कनेक्टिविटी और तकनीकी सुविधाएँ अपर्याप्त थीं, जिसके कारण स्थानीय नवाचार या डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा नहीं मिल पाया। इस क्षेत्रीय असमानता के कारण उद्यमिता के अवसर भी असमान रूप से वितरित रहे।

3. नियामकीय जटिलताएँ और नीतिगत अनिश्चितता

यद्यपि 'स्टार्टअप इंडिया' पहल ने कई सुधार किए, लेकिन मई 2017 तक पंजीकरण, टैक्स-छूट, फंडिंग अनुमोदन, श्रम कानून अनुपालन तथा IPR सुरक्षा से जुड़े प्रक्रियात्मक चरण जटिल माने जाते थे। नए उद्यमों को कंपनी पंजीकरण, स्थानीय निकायों से अनुमति, श्रम एवं पर्यावरण मानकों की पूर्ति में अत्यधिक समय लग जाता था। बदलती नीतियों तथा अस्पष्ट दिशानिर्देशों के कारण उद्यमों को भविष्य की योजना बनाने में कठिनाई होती थी। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भी प्रभावित होता था।

4. कौशल का अभाव और मानव संसाधन से संबंधित बाधाएँ

भारत की जनसंख्या बड़ी जरूर है, पर स्टार्टअप्स को आवश्यक *विशिष्ट कौशल* जैसे—डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फुल-स्टैक डिवेलपमेंट, डिज़ाइन थिंकिंग,

अनुसंधान एवं विकास आदि में कुशल मानव संसाधन मई 2017 तक सीमित था। देश के इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले अधिकांश युवा *उद्योग की अपेक्षित गुणवत्ता* के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं थे। इसके अलावा प्रतिभा के पलायन के कारण भी अनेक नवाचार संभावनाएँ प्रभावित होती थीं। स्टार्टअप्स उच्च कौशल वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन देने में बड़ी कंपनियों की तुलना में सक्षम नहीं थे।

5. बाजार तक पहुँच की कठिनाई और प्रतिस्पर्धा का दबाव

भारतीय स्टार्टअप्स को शुरुआती वर्षों में बाजार में प्रवेश करने, उपभोक्ता-आधार बनाने, विश्वसनीयता प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाइयाँ आती थीं। ई-कॉमर्स, फिनटेक तथा शहरी सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी। बड़ी कंपनियाँ—जो अधिक पूंजी और संसाधनों से लैस थीं—नए स्टार्टअप्स को बाजार से बाहर कर सकती थीं। ग्राहक अधिग्रहण लागत (CAC) भी बहुत अधिक थी, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती थी।

6. बौद्धिक संपदा (IPR) सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ

भारत में 2017 तक पेटेंट प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी, महंगी और जटिल थी। अनेक नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स अपने उत्पादों या तकनीक का पेटेंट नहीं करा पाते थे, जिससे उनकी बौद्धिक संपदा चोरी या अनुकरण का जोखिम बढ़ जाता था। IPR विशेषज्ञता, कानूनी सहयोग और सरकारी प्रोत्साहन की कमी नवाचार को सीमित करती थी। विदेशी बाजारों में पेटेंट आवेदन की लागत तो और भी अधिक थी, जिसे अधिकांश उद्यम वहन नहीं कर पाते थे।

7. R&D एवं नवाचार निवेश का निम्न स्तर

भारत का कुल R&D व्यय GDP का लगभग 0.8% (2016 तक) था, जो चीन, कोरिया, इज़राइल और विकसित देशों की तुलना में बहुत कम था। स्टार्टअप्स और MSMEs में R&D के लिए पूंजी का अभाव था। अधिकांश भारतीय स्टार्टअप्स *प्रतिलिपि आधारित मॉडल* अपनाते थे, अर्थात विदेशी अवधारणाओं का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन करते थे। वास्तविक तकनीकी नवाचार सीमित था, और विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग भी अपेक्षित स्तर पर नहीं था।

8. विफलता का सामाजिक भय और उद्यमी संस्कृति का अभाव

भारतीय समाज में उद्यमिता को अभी भी जोखिमपूर्ण माना जाता है। असफलता को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जिससे युवा सुरक्षित नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। पारिवारिक समर्थन, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और दीर्घकालिक उद्यमी दृष्टि सभी अभी विकासशील अवस्था में थे। इसके विपरीत, अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों में असफलता को सीखने की प्रक्रिया माना जाता है, जिससे नवाचार बढ़ता है।

9. महिला उद्यमियों एवं ग्रामीण उद्यमिता के सामने विशेष बाधाएँ

महिला उद्यमियों को पूंजी, प्रशिक्षण, बाज़ार तक पहुँच, सामाजिक प्रतिबंध, पारिवारिक दायित्व तथा सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, बैंक–सहयोग, आधुनिक उपकरण, इंटरनेट तथा व्यापारिक नेटवर्क की कमी प्रमुख बाधाएँ रहीं।

10. वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तन की तीव्रता

दुनिया में तकनीकी परिवर्तन अत्यधिक तेज़ गति से हो रहा था। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुनौतीपूर्ण था, विशेषकर तब जब अनुसंधान में निवेश और तकनीकी दक्षता सीमित हों।

इन सभी समस्याओं से स्पष्ट है कि भारत में उद्यमिता एवं नवाचार विगत वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, परंतु वित्त, अवसंरचना, कौशल, नीतिगत समर्थन और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित चुनौतियाँ इसकी गति को सीमित करती हैं। इन बाधाओं के समाधान हेतु समन्वित नीतियों, निवेश, शिक्षा–सुधार और तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता है।

सुझाव / उपाय

भारत में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम की तीव्र वृद्धि के बावजूद कई संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियाँ मौजूद थीं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु बहु-स्तरीय सुधारों की आवश्यकता है, जिनमें सरकारी नीतियाँ, वित्तीय तंत्र, शिक्षा-व्यवस्था, औद्योगिक अवसंरचना एवं सामाजिक दृष्टिकोण सभी का योगदान आवश्यक है। भारत में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समन्वित, बहु-आयामी और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। उद्यमिता को मजबूत करने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नवत हैं -

सबसे पहले, नीति-स्तर पर स्पष्ट, स्थायी और उद्यमी-अनुकूल वातावरण तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि बार-बार होने वाले नियामकीय परिवर्तन और जटिल प्रक्रियाएँ स्टार्टअप्स की प्रगति को बाधित करती हैं। इसके लिए *Ease of Doing Business* ढांचे के तहत कंपनी पंजीकरण, श्रम कानूनों, कर प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को और अधिक सरल तथा डिजिटल बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली कर–छूट, पेटेंट पंजीकरण शुल्क में कमी, तथा नवोन्मेषी क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन आवश्यक हैं।

दूसरे, वित्त–उपलब्धता किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम की आधारशिला होती है। भारत में आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स को विशेष रूप से बीज–निधि (Seed Funding), वेंचर कैपिटल तक पहुँच और ऋण–आधारित सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकारी कोष को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाना चाहिए, तथा बैंकिंग प्रणाली को भी पारंपरिक संपार्श्विक (Collateral) आधारित ऋण प्रणाली से आगे बढ़कर क्रेडिट–गारंटी आधारित ऋण योजनाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए माइक्रो–फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी विशेष उद्यमिता योजनाओं का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है।

तीसरे, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु स्थापित किया जाना चाहिए। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय अब भी बहुत कम है, इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को अनुसंधान एवं विकास पर निवेश बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर, टेक-लैब, इनोवेशन हब और स्टार्टअप सेल स्थापित करने से युवा शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यवसाय में रूपांतरित करने का अवसर मिलेगा।

चौथे, उद्यमिता–शिक्षा का विस्तार समय की प्रमुख आवश्यकता है। स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसमें रचनात्मकता, समस्या–समाधान क्षमता, जोखिम–सहनशीलता तथा नेतृत्व कौशल को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही, *स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया* जैसी पहलों से प्राप्त अवसरों का उपयोग कर युवाओं को बाज़ार की वर्तमान मांगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

पाँचवें, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना भी अत्यंत आवश्यक है। विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, परिवहन, लॉजिस्टिक सुविधाएँ और डिजिटल भुगतान प्रणाली स्टार्टअप्स की सफलता के मूल तत्व हैं। विशेष रूप से टियर–2 और टियर–3 शहरों में तकनीकी और भौतिक अवसंरचना का विकास स्टार्टअप संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उपर्युक्त उपाय भारत के उद्यमिता एवं स्टार्टअप परिदृश्य को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक हैं। वित्त, अवसंरचना, कौशल, अनुसंधान, नीतिगत सुधार और सामाजिक समर्थन—इन सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयास करके भारत नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को सुदृढ़ कर सकता है। यदि ये सुधार विस्तृत स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो भारत न केवल स्टार्टअप्स की संख्या और निवेश को बढ़ा सकेगा, बल्कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता भी रखता है।

निष्कर्ष

भारत में उद्यमिता और नवाचार केवल आर्थिक प्रगति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के वाहक भी हैं। युवाओं के सृजनात्मक विचार, प्रौद्योगिकी का प्रसार और सरकारी समर्थन भारत को 21वीं सदी की स्टार्टअप महाशक्ति बना सकते हैं। भविष्य का भारत ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता पर आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाएगा।

भारत में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास 2010 के बाद विशेष रूप से तीव्र गति से हुआ। मई 2017 तक उपलब्ध आँकड़ों और नीतिगत पहलों से स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक उभरती हुई नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, युवा आबादी की ऊर्जा, तकनीकी कौशल में वृद्धि तथा सरकारी कार्यक्रमों—डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया—ने देश में उद्यमशील वातावरण को मजबूत किया है।

स्टार्टअप्स ने न केवल रोजगार सृजन में योगदान दिया है, बल्कि वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस, सामाजिक नवाचार, ग्रामीण–शहरी समन्वयन, और उत्पादकता वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों ने तकनीक के माध्यम से उपभोक्ताओं, किसानों, छात्रों और व्यवसायों तक नई सुविधाओं को पहुँचाया। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम युवा नवाचारों का केंद्र बनकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भागीदार बना है। यद्यपि यह भी सच है कि भारत की उद्यमिता यात्रा पूरी तरह चुनौतियों से मुक्त नहीं रही। आर्थिक और वित्तीय जोखिम, सीमित संरचनात्मक अवसंरचना, तकनीकी कौशल का अभाव, नियामकीय जटिलताएँ, R&D निवेश में कमी, बौद्धिक संपदा की अपर्याप्त सुरक्षा, और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ स्टार्टअप्स की गति को सीमित करती रही हैं। क्षेत्रीय असमानताएँ दर्शाती हैं कि उद्यमिता का विकास अभी भी कुछ चुनिंदा महानगरों तक केंद्रित है और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया है।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु वित्तीय पहुँच में सुधार, नीति-सरलीकरण, कौशल-विकास कार्यक्रमों का विस्तार, विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग को बढ़ावा, महिला एवं ग्रामीण उद्यमिता को प्राथमिकता, तथा R&D निवेश में वृद्धि आदि सुधारों के माध्यम से भारत नवाचार-अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता और नवाचार भारत के आर्थिक विकास की नई दिशा प्रस्तुत कर रहे हैं। पारंपरिक उद्योगों और रोजगार मॉडलों के स्थान पर अब तकनीक-आधारित, ज्ञान-आधारित और नवाचार-चालित विकास मॉडल तेजी से उभर रहा है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, अवसर विस्तार तथा समावेशी विकास के नए द्वार भी खोलता है। सरकार,

उद्योग और शैक्षणिक संस्थान मिलकर उद्यमिता के लिए समर्थ परिवेश तैयार करके और चुनौतियों को दूर करने हेतु समन्वित प्रयास करके भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता बनाने में सफल हो सकता है। स्टार्टअप्स न केवल रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक सशक्त भूमिका दिलाने में भी सक्षम हैं। उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति भारत के लिए केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास की एक व्यापक रणनीति है। यह रणनीति युवाओं को सशक्त बनाती है, उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाती है और समाज में परिवर्तन की नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि इन संभावनाओं का सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो भारत 21वीं सदी में विश्व का प्रमुख नवाचार-केन्द्र बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है।

संदर्भ

1. Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2010). *Handbook of entrepreneurship research: An interdisciplinary survey and introduction*. Springer.
2. Agarwal, R., Audretsch, D., & Sarkar, M. B. (2010). Knowledge spillovers and strategic entrepreneurship. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 4(4), 271–283.
3. Aghion, P., & Howitt, P. (2009). *The economics of growth*. MIT Press.
4. Audretsch, D. B. (2012). Entrepreneurship research. *Management Decision*, 50(5), 755–764.
5. Bhide, A. (2000). *The origin and evolution of new businesses*. Oxford University Press.
6. Chandra, R., & Raj, R. S. N. (2009). Innovations and entrepreneurship in India: A study of the growth dynamics. *Indian Journal of Industrial Relations*, 45(2), 241–255.
7. Chesbrough, H. (2006). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.
8. Dutz, M. A. (Ed.). (2007). *Unleashing India's innovation: Toward sustainable and inclusive growth*. World Bank.
9. Economic Survey of India. (2016). Ministry of Finance, Government of India.
10. Ernst & Young. (2015). *India's startup ecosystem: A new paradigm for growth and innovation*. EY India Report.
11. Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2005). *The Oxford handbook of innovation*. Oxford University Press.
12. Government of India. (2016). *Start-up India Action Plan*. Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT).
13. Gupta, A., & Dutta, S. (2016). India innovation and competitiveness. *Global Innovation Index Report 2016*. INSEAD & WIPO.
14. Klein, P. (2010). *The capitalist and the entrepreneur*. Ludwig von Mises Institute.
15. KPMG. (2014). *Startup India: Impact analysis and industry trends*. KPMG India.
16. Lerner, J. (2009). *Boulevard of broken dreams: Why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed—and what to do about it*. Princeton University Press.
17. MIT Technology Review. (2015). *Innovators under 35: Asia Report*. MIT Press.
18. NASSCOM. (2015). *Startup India: A NASSCOM perspective on building innovation-driven economy*. NASSCOM India Report.

19. NASSCOM. (2016). *Startup India—The next growth frontier*. NASSCOM Startup Report.
20. OECD. (2010). *Entrepreneurship, SMEs and innovation*. OECD Publishing.
21. Planning Commission of India. (2013). *Twelfth Five-Year Plan (2012–2017): Faster, More Inclusive and Sustainable Growth*. Government of India.
22. Prasad, C. S., & Sridhar, V. (2009). Entrepreneurship and skill development. *Journal of Entrepreneurship*, 18(1), 33–50.
23. Ramanathan, H. N. (2013). Innovation and SMEs in India. *Economic and Political Weekly*, 48(3), 24–29.
24. Reserve Bank of India. (2015). *Financial stability report*. RBI Publications.
25. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press. (Reprinted).
26. Sharma, S. (2014). Entrepreneurship development in India: Emerging issues and challenges. *International Journal of Business Management*, 2(4), 15–23.
27. Startup Genome. (2016). *Global Startup Ecosystem Ranking Report 2016*. Startup Genome Project.
28. Subrahmanya, M. H. B. (2015). Technological innovations and small and medium enterprises (SMEs) in India. *Tech novation*, 30(12), 939–948.
29. UNCTAD. (2016). *World Investment Report 2016: Investor Nationality*. United Nations Publications.
30. World Bank. (2014). *Doing Business Report 2014: Understanding regulations for small and medium-size enterprises*. World Bank Group.
31. World Economic Forum. (2015). *Global Competitiveness Report 2015–2016*. WEF.